हमारे बारे में

मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की जिम्मेदारी दोनों मंत्रालयों, यानी शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) तथा शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमओयूईपीए) के बजट, भुगतान तथा वित्त कार्यों का संचालन करना है। हरेक मंत्रालय का सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है और ये संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा नियंत्रक की मदद से इन कार्यों को अंजाम देता है।

मुख्य लेखा नियंत्रक भुगतान व लेखा संगठन का प्रमुख होता है। उसकी सहायता के लिए दो लेखा नियंत्रक, चार उप लेखा नियंत्रक तथा 28 वेतन एवं लेखा अधिकारी होते हैं। इस मंत्रालय के भुगतान तथा लेखा कार्य 13 वेतन तथा लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा संपन्न किए जाते हैं; जिनमें से 6 नई दिल्ली में, 2 चेन्नई में, 2 कोलकाता में, 2 मुम्बई में तथा एक शिलॉन्ग में है। मुद्रण विभाग तथा के. लो. नि. में बजट, वित्त तथा लेखा कार्यों के संपादन के क्रम में, सीसीए के प्रतिनिधियों की इन विभागों में वित्त अधिकारियों (एफओ) तथा डिविजनल अकाउंट्स (डीए) के रूप में नियुक्ति की जाती है। ये एफओ तथा डीए सीसी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है। 16 एफओ और लगभग 350 डीए होते हैं। मंत्रालय में लगभग 429 व्यय इकाइयां होती हैं, जिनमें से 319 चेक हस्ताक्षर इकाइयां (सीडीडीओ) तथा 110 गैर-चेक हस्ताक्षर इकाइयां (एनसीडीडीओ) होती हैं।

मुख्य लेखा नियंत्रक कई बोर्ड तथा मंत्रालय की परामर्श समिति में शामिल होते हैं, जिनमें केन्द्रीय निर्माण कार्य भी शामिल है, जो 5 करोड़ से ऊपर के प्रॉजेक्ट की जांच कर उसे मंजूरी प्रदान करता है तथा उन अपवाद मामलों को भी देखता है जो बोर्ड के पास आते हैं।